P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-4* December- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

"नगरीय उपान्त प्रदेश के संपोषणीय विकास हेतु नियोजन प्रस्ताव–बागपत कस्बा का एक भौगोलिक अध्ययन"

Planning Proposal for Sustainable Development of Urban Sub-Region - A Geographical Study of Baghpat Town"

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 28/12/2020, Date of Publication: 29/12/2020

संदीप कुमार
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलिज, बड़ौत,
बागपत, उ०प्र०, भारत

सारांश

नगरीकरण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है। नगरीकरण ग्रामीण एवं नगरीय उपान्त प्रदेश को प्रभावित करता है। नगरीकरण के कारण ही भूमि उपयोग प्रतिरूप में तीव्रगति से परिवर्तन हो रहा है। आन्तरिक एवं वाहय भू–आकृति तीव्रगति से बदल रही है। बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव नगर पर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे न केवल नगर का फैलाव हो रहा है, बल्कि सेवाओं का भी विकास हो रहा है। नगरीकरण ने उपान्त प्रदेश की आधारभूत संरचना को विकसित कर नये–नये कस्बों के विकास हेतु बुनियाद रखी है। परिवहन सुविधाओं ने नगर के फैलाव को गति प्रदान की है। अनियोजित नगरीकरण ने विविध प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। व्यापारिक गति विधियों के विकसित होने से संरचना में परिवर्तन हुआ है। नगरीय उपान्त प्रदेश में द्वितीयक क्रम की सेवाऐं तीव्रगति से विकसित हुई हैं। नगरीय उपान्त प्रदेश के सतत एवं सन्तुलित विकास हेतु नियोजन की आवश्यकता है, जिससे वहां भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याऐं उत्पन्न न हो सकें।

Urbanization is a continuous process. It is the mainstay of physical, social, economic and cultural change. Urbanization affects the rural and urban suburbs. Due to urbanization, the land use model is undergoing rapid changes. The internal and external landscape is changing rapidly. The pressure of meeting the basic needs of the growing population is increasing day by day on the city, which is not only expanding the city, but also developing services. Urbanization has laid the foundation for the development of new towns by developing the infrastructure of the province. Transport facilities have accelerated the spread of the city. Unplanned urbanization has given rise to a variety of problems. The structure has changed with the development of trading speed methods. Services of secondary order have developed rapidly in the urban sub-region. There is a need for planning for the sustainable and balanced development of the urban sub-region, so that physical, social, economic and cultural problems cannot arise there.

मुख्य शब्द : नगरीय उपान्त प्रदेश, प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन, सेवा केन्द्र, संपोषणीय विकास।
Urban Provinces, Influence, Social, Economic, Change, Service Center, Sustainable Development.

प्रस्तावना

जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि होने के कारण नगरीय जनसंख्या में भी तीव्रगति से परिवर्तन हुआ है। नगरीकरण के कारण न केवल नगरीय जनसंख्या के आकर में परिवर्तन हुआ है बल्कि नगरों के भौतिक विस्तार में भी परिवर्तन हुआ है। नगरीकरण के कारण उच्च स्तर की सुविधाओं का विकास हुआ है। इन सुविधाओं के विकास ने जनसंख्या की निर्भरता को कम कर उनके मध्य स्थित औसत दूरी को कम किया है। नगरों के फैलाब के कारण उपान्त प्रदेश विकसित हुआ है। यह मुख्य नगर से इत्र तथा नगरीय परिधि पर ग्रामीण व नगरीय सुविधाओं से सुसज्जित क्षेत्र है, जो नगर के फैलाब के कारण नगर के चारों ओर विकसित हुआ है। नगर के विकसित होने से उपान्त प्रदेश में सुविधाओं का विकास हुआ है। यहां का भूमि उपयोग प्रतिरूप तीव्रगति से परिवर्तित हुआ है।

उपान्त प्रदेश में कृषि का प्रतिरूप बदल रहा है। इस क्षेत्र में हार्टीकल्चर की कृषि को वरीयता प्रदान की जाती है। यहां पर सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं में विकास के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में तीव्रगति से परिवर्तन हुआ है।

नगरीकरण के कारण जहां एक ओर सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय समस्याओं तथा भौतिक समस्याओं का भी जन्म हुआ है। भूमि की उच्च कीमत, अनियोजित विकास, छोटी–छोटी गलियां जल निकासी की समस्या, दूषित पर्यावरण, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण इत्यादि के कारण नगर का विकास परिधि की ओर तीव्रगति से होने लगा है, जिसके कारण नगर का फैलाव तीव्रगति से हो रहा है। इसके साथ आवासीय कालोनियों के विकसित होने तथा उद्योग–धन्धों के वाहय भाग पर विकसित होने से नगरीय उपान्त प्रदेश का विकास तीव्रगति से हो रहा है। उपान्त प्रदेश में भूमि की उच्च उपलब्धता के कारण न केवल भूमि का मूल्य निम्न है, बल्कि विस्तृत क्षेत्र के कारण विविध प्रकार के उद्योग–धन्धों की स्थापना तथा गोदामों इत्यादि के विकास हेतु उपयुक्त सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

नगरीय उपान्त प्रदेश की संकल्पना

टी०एल० स्मिथ नामक समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम 'नगरीय उपान्त' शब्द का प्रयोग किया। उन्होने इससे सम्बन्धित समस्याओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। इन्होने नगर की प्रशासकीय सीमा के बाहर निर्मित क्षेत्र को नगरीय उपान्त का नाम दिया। साल्टर ने 1940 में उपान्त पेटी को परिभाषित किया। इन्होने बताया कि ''यह पेटी नगरीय व ग्रामीण भूमि उपयोग का मिश्रित रूप है तथा नगर के बाहर फैली यह पेटी भूमि उपयोग की विशेषताओं के आधार पर कई वर्गो में विभाजित की जा सकती है। यह पेटी गम्भीर एवं जटिल समस्याओं से ग्रहस्त होती है, जिसके निदान हेतु उचित नियोजन की आवश्यकता होती है।'' आर०ई० डिकिन्सन ने इसे नगर की बाहय सीमा पर नगरीय व ग्रामीण भूमि उपयोग के मध्यवर्ती भाग में एक क्षेत्र पाया जाता है जो नगर व गांव दोनों की विशेषताओं को धारण करता है तथा यह क्षेत्र नगरीय प्रसार से पीड़ित रहता है। नगरीय उपान्त प्रदेश वास्तव में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के मध्य विस्तृत वह भू–भाग है जो ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की विशेषताओं को धारण करता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बागपत कस्बा को चयनित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 40 किमी० की दूरी पर उत्तर पूरब दिशा में अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य के मध्य अवस्थित एक छोटा सा कस्बा है, जिसका विकास जनपद मुख्यालय घोषित होने के बाद तीव्रगति से हुआ है। यह दिल्ली–सहारनपुर मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित है। बागपत कस्बा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2.88 वर्ग किमी० है। यहां की कुल जनसंख्या 50310 तथा कुल साक्षरता 61.43 प्रतिशत है। यहां का औसत लिंगानुपात 903 तथा औसत जनसंख्या घनत्व 17469 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० है। यह कस्बा 25 बार्डो में विभाजित है। बागपत कस्बा के समीप अग्रवाल मंड़ी टटीरी तथा खेकड़ा कस्बा अवस्थित हैं। 1997 में मेरठ जनपद से पृथक करके बागपत जनपद का निर्माण किया गया। जिला मुख्यालय बनने के पश्चात इस कस्बें का विकास तीव्रगति से हुआ है। इसके साथ ही नगरीय उपान्त प्रदेश में तीव्रगति से परिवर्तन हुआ है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1. नगरीय उपान्त प्रदेश के संपोषणीय विकास के कारकों को ज्ञात करना।
2. नगरीय उपान्त प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का मूल्यांकन करना।
3. नगरीय उपान्त प्रदेश की समस्याओं को ज्ञात करना तथा उनके निवारण हेतु रणनीति तैयार करना।

शोध परिकल्पनाऐ

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु निम्न शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. नगरीय उपान्त प्रदेश का विकास नगर की अद्यः संरचनात्मक विकास का परिणाम है।
2. नगर के उपान्त प्रदेश में सेवा केन्द्रों का विकास तीव्रगति से होता है।
3. नगरीय उपान्त प्रदेश में आर्थिक क्रिया–कलापों में तीव्रगति से परिवर्तन होता है।

आँकड़ों का संग्रह एवं विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन अध्ययन क्षेत्र से नमूना सर्वे, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अन्वेषण, पर्यवेक्षण तथा प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग करके प्राप्त किये गये हैं। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद बागपत, नगरपालिका कार्यालय बागपत, तथा जिला गजेटियर्स जनपद बागपत से प्राप्त किये है। प्रस्तुत आँकड़ों का सारणीयन कर आँकड़ों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से शोध समस्या के स्तर तथा प्रतिरूप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। नगर के प्रभाव क्षेत्र तथा नगरीय उपान्त प्रदेश की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने हेतु अनुभवात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है।

पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा

नगरीय उपान्त प्रदेश के विकास तथा उसकी समस्याओं एवं समाधान के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों ने शोध कार्य पूर्ण किये हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये शोध कार्यों को कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।– नेहा, गोयल (2011)[1] ने अपना शोध पत्र फरीदाबाद नगर के उपान्त प्रदेश के विकास एवं नियोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। इन्होने अपने शोध में पाया कि नगरीय उपान्त प्रदेश में नगरीकरण तथा भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। नगरीय उपान्त प्रदेश में मिश्रित कार्यो की प्रधानता इसके तीव्र विकास का प्रमुख कारण है। मिनसन किम (2012)[2] ने अपना शोध पत्र मुम्बई नगर के उपान्त प्रदेश के निवासियों की आजीविका का अध्ययन किया।

इन्होने पाया कि उपान्त प्रदेश के भूमि उपयोग में जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या के कार्यो में तीव्रगति से परिवर्तन हुआ है। डेनियल मैना युओ (2013)[3] ने अपना शोध कार्य नगरीय उपान्त प्रदेश में अनिवासित क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। इन्होने अपने शोध में पाया कि ग्रामीण–नगरीय उपान्त प्रदेश में निवासित क्षेंत्र का विकास तीव्रगति से होता है, जबकि अनिवासित क्षेत्र का विकास बहुत धीरे–धीरे होता है नगरीकरण के कारण न केवल आवास की मांग बढ़ती है बल्कि अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। कमल आसिफ (2014)[4] ने अपना शोध कार्य अलीगढ़ नगर के उपान्त प्रदेश में कृषि भूमि के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। इन्होने नगरीय उपान्त प्रदेश में भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु नगरीकरण तथा नगरीय फैलाब व ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होना बताया। निशा (2015)[5] ने जम्मू नगर के उपान्त प्रदेश का अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होने नगरीय उपान्त प्रदेश के विकास को समय का प्रतिफल बताया है, जो नगर के चारों ओर एक संक्रमण पट्टी के रूप में विकसित होता है। इसका विकास नगर के विकास पर निर्भर करता है। इसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए संसाधनों व सेवा केन्द्रों का विकसित होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेहा एवं कृष्ण कुमार (2016)[6] ने अपने शोध में पाया कि नगरीय उपान्त प्रदेश का विकास नगरीय फैलाब का परिणाम है। यद्यपि ग्रामीण एवं नगरीय उपान्त प्रदेश के मध्य सीमा रेखा खीचना संभव नही है, फिर भी कुछ मापकों के आधार पर इनका विभाजन किया जा सकता है। इन्होने इस प्रदेश को तीव्रगति से परिवर्तित प्रदेश की संज्ञा दी। यहां पर नये कस्बों के विकास के केन्द्र विकसित होते हैं। नेंग्रो जा, शाह एवं भट्ट (2017)[7] ने अपना शोध पत्र श्रीनगर शहर के ग्रामीण–नगरीय उपान्त प्रदेश में भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। इन्होने अपने शोध में पाया कि उपान्त प्रदेश के भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हैं। भूमि उपयोग में तीव्रगति से परिवर्तन का प्रमुख कारण वर्तमान समय में जनसंख्या की आर्थिक क्रिया–कलापों में परिवर्तन हैं। मृणालिनी गोस्वामी (2018)[8] ने अपना शोध पत्र नगरीय उपान्त प्रदेश भू–आकृतिक परिवर्तन तथा सन्तुलित विकास एवं प्रबन्धन के सन्र्दभ में प्रस्तुत किया। इन्होने अपने शोध में पाया कि ग्रामीण–नगरीय उपान्त प्रदेश का सन्तुलित विकास, प्रबन्धन के आधार पर किया जा सकता है, जिससे वहां पर उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रथम अवस्था में ही किया जाना संभव होगा। कुमार एवं सिन्हा (2019)[9] ने ग्रामीण नगरीय उपान्त प्रदेश नगरीय सीमा के बाहर विकसित एक पेटी है, जिसका विकास नगरीकरण के कारण हुआ है। यहां पर ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के मिश्रित कार्यो का संकेन्द्रण पाया जाता है। नगर से बाहर की ओर जाने पर कार्यो की विविधता घटती जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण

अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा में तीव्र नगरीकरण 1997 के पश्चात जिला मुख्यालय बनने के बाद हुआ है। जिला मुख्यालय बनने से पूर्व यहां पर नगरीकरण की दर धीमी थी। इसके पश्चात ही नगरीय फैलाव हुआ है तथा नगरीय उपान्त प्रदेश विकसित हुआ है। अध्ययन क्षेत्र कस्बा बागपत में नगरीकरण को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–1

कस्बा बागपत में नगरीकरण, 1991–2011

वर्ष	नगरीय जनसंख्या	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत में)
1991	24939	–
2001	36384	45.89
2011	50310	38.26

स्रोत जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद बागपत वर्ष, 1991, 2001, व 2011

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1991 में नगरीय जनसंख्या 24939 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 36384 तथा 2011 में बढ़कर 50310 हो गयी है। 1991–2001 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में 45.89 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2001–2011 की अवधि में 38.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की दर उच्च है, जिसका प्रमुख कारण नगर का फैलाब तथा ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर पलायन व विविध प्रकार की सुविधाओं का विकसित होना है।

नगरीय उपान्त प्रदेश–कस्बा बागपत की विशेषताऐं

कस्बा बागपत के नगरीय उपान्त प्रदेश की विशेषताओं को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–2

कस्बा बागपत के नगरीय उपान्त प्रदेश की विशेषताऐं, नवम्बर 2020

कुल जनसंख्या	103744
औसत जनसंख्या घनत्व	552
औसत लिंगानुपात	937
औसत साक्षरता	71.30 प्रतिशत
कार्यशील जनसंख्या	48..85 प्रतिशत
प्राथमिक क्रिया–कलापों में संलग्न जनसंख्या	58.72 प्रतिशत
द्वितीयक क्रिया–कलापों में संलग्न जनसंख्या	27.45 प्रतिशत
तृतीयक क्रिया–कलापों में संलग्न जनसंख्या	13.83 प्रतिशत

स्रोत शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों की गणना पर आधारित, नवम्बर 2020

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र कस्बा बागपत के नगरीय उपान्त प्रदेश की कुल जनसंख्या 103744 तथा औसत जनसंख्या घनत्व 552 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० प्राप्त हुआ है। यहां पर औसत लिगांनुपात 937 तथा औसत साक्षरता 71.30 प्रतिशत है। यहां पर कुल कार्यशील जनसंख्या 48.85 प्रतिशत है। नगरीय उपान्त प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या विविध प्रकार के कार्यो में संलग्न है, जिसमें प्राथमिक क्रिया–कलापों में 58. 72 प्रतिशत, द्वितीयक क्रिया–कलापों में 27.45 प्रतिशत तथा तृतीयक क्रिया–कलापों में 13.83 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है। अध्ययन क्षेत्र के उपान्त प्रदेश में उद्योग–धन्धों तथा व्यापारिक गतिविधियों का अभाव पाया गया है। सड़क मार्गो के सहारे–सहारे यद्यपि कुछ औद्योगिक इकाईया स्थापित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में केवल ईट, उद्योग तथा गुड़ उद्योग ही स्थापित हैं। यहां पर कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्रिया–कलापों में अधिकांश जनसंख्या संलग्न है।

नगरीय उपान्त प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का वितरण

अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा के उपान्त प्रदेश में सेवा केन्द्रों का विकास जनपद मुख्यालय बनने के पश्चात हुआ है। यहां पर उच्च क्रम की सेवाऐं भी विकसित हुई है। जिनमें स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग–धन्धों तथा दैनिक बाजार इत्यादि प्रमुख हैं। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय उपान्त प्रदेश में अवस्थित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के वितरण को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–3

बागपत कस्बा के नगरीय उपान्त प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का वितरण, नबम्बर 2020

क्र०सं०	सुविधाऐं	संख्या	औसत अन्तरालन (किमी० में)	औसत जनंसख्या निर्भरता
1.	प्राथमिक विद्यालय	58	2.32	1789
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	35	2.98	2964
3.	इण्टरमीडिएट कॉलिज	16	4.41	6484
4.	स्नातक महाविद्यालय	7	6.67	14821
5.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	5	7.90	20749
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2	12.48	51872
7.	निजि चिकित्सालय	10	5.58	10374
8.	बैंकिग सुविधाऐं	8	6.24	12968
9.	दैनिक बाजार	6	7.20	17291
10.	साप्ताहिक बाजार	14	4.72	7410
11.	पैट्रोल पम्प	12	5.10	8645
12.	गैस एजेन्सी	4	8.83	25936
13.	कृषि सेवा केन्द्र	15	4.56	6916
14.	ईंट उद्योग	18	4.16	5764
15.	गुड़ उद्योग	30	3.22	3458

स्रोत शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों की गणना पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के नगरीय उपान्त प्रदेश में सुविधाओं के मध्य औसत अन्तरालन 5.76 किमी० तथा औसत जनसंख्या निर्भरता 432 है। नगरीय उपान्त प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के मध्य औसत अन्तरालन 2.32 किमी०, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य 2.98 किमी०, इण्टरमीडिएट कॉलिज के अन्तर्गत 4.41 किमी०, स्नातक महाविद्यालयों के अन्तर्गत 6.67 किमी० तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के मध्य औसत अन्तरालन 12.48 किमी० तथा निजी चिकित्सालयों के मध्य औसत दूरी 5.58 किमी० है। बैंकिग सुविधाऐं 6.24 किमी० की औसत दूरी पर अवस्थित हैं। दैनिक बाजार 7. 20 किमी० तथा साप्ताहिक बाजार 4.72 किमी०, की औसत दूरी पर अवस्थित हैं। पैट्रोल पम्प की सुविधा 5.10 किमी० तथा गैस ऐजेन्सी की सुविधा 8.83 किमी० की औसत दूरी पर अवस्थित हैं। कृषि सेवा केन्द्र 4.56 किमी०, ईट उद्योग 4.16 किमी० तथा गुड डद्योग 3.22 किमी० की औसत दूरी पर अवस्थित है। उपरोक्त आँकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नगरीय उपान्त प्रदेश में सेवा केन्द्रों का विकास हुआ है, जिससे नगरीय उपान्त प्रदेश जनसंख्या निर्भरता व औसत अन्तरालन में कमी हुई है।

नगरीय उपान्त प्रदेश की समस्याऐं

अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा का नगरीय उपान्त प्रदेश वर्तमान समय में निम्न समस्याओं से जूझ रहा है–

1. अनियोजित विकास
2. यातायात एवं परिवहन सुविधाओं के सीमित साधन
3. वृहत उद्योग–धन्धों का अभाव
4. लधु एवं कुटीर उद्योग–धन्धों का पतन
5. गांव से नगर की ओर पलायन
6. गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दर
7. पर्यावरण प्रदूषण की समस्या
8. जल प्रदूषण की समस्या
9. भूमि उपयोग की समस्या
10. उच्च जन्म दर

नगरीय उपान्त प्रदेश में भूमि उपयोग प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा का भूमि उपयोग प्रतिरूप निरन्तर बदल रहा है। भूमि उपयोग प्रतिरूप में सर्वाधिक परिवर्तन परिवहन सुविधाओं वाले क्षेत्र में हुआ है। इसके साथ ही विर्निमाण के क्षेत्र में तीव्रगति से परिवर्तिन हुआ है। अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा के नगरीय उपान्त प्रदेश में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–4

बागपत कस्बा के नगरीय उपान्त प्रदेश के भूमि उपयोग में परिवर्तन, वर्ष 1991–2011

क्र०स०	मद	भूमि उपयोग क्षेत्र (प्रतिशत में)			परिवर्तन 1991–2011
		1991	2001	2011	
1.	वनीय क्षेत्र	1.36	1.05	1.13	–0.23
2.	बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि	3.88	3.42	1.45	–2.43
3.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	6.32	8.67	11.74	5.42
4.	कृषि योग्य बंजर भूमि	4.37	3..64	1.50	–2.87
5.	चारागाह	0.22	0.10	0.06	–0.16
6.	उद्यानों एवं बागानों की भूमि	1.05	0.56	0.14	–0.91
7.	वर्तमान परती भूमि	2.65	1.87	0.93	–1.72
8.	अन्य परती भूमि	1.84	1.35	0.86	–0.98
9.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	78.31	79.34	82.19	3.88

स्रोतः–जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद बागपत, 1991, 2001 व 2011,

उपोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के नगरीय उपान्त प्रदेश के भूमि उपयोग प्रतिरूप में तीव्रगति से परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1991 में वनीय क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि 1.36 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 1.13 प्रतिशत रह गयी है। वर्ष 1991 में बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि का भाग 3..88 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 में घटकर 1.45 प्रतिशत रह गया है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि के भाग में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भूमि सड़कों, आवासों, उद्योग–धन्धों तथा विविध प्रकार की संस्थाओं के अन्तर्गत संलग्न है। कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र उक्त अवधि में 2.87 प्रतिशत कम हुआ है। चारागाह का क्षेत्र 0.16 प्रतिशत तथा उद्यानों एवं बागानों के क्षेत्र में 1991–2011 की अवधि में 0.91 प्रतिशत क्षेत्र कम हुआ है। वर्तमान परती भूमि का क्षेत्र वर्ष 1991 में 2.65 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 में घटकर 0.93 प्रतिशत रह गया है। अन्य परती भूमि के क्षेत्र में 0.98 प्रतिशत भाग की कमी अंकित की गयी है। वर्ष 1991 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 78.31 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 82.19 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग में परिवर्तन को स्पष्ट किया जा सकता है।

नगरीय उपान्त प्रदेश हेतु नियोजन

अध्ययन क्षेत्र बागपत कस्बा के नगरीय उपान्त प्रदेश के सत्त एवं सन्तुलित विकास हेतु निम्न प्रकार से नियोजन किया जा सकता है–

1. सेवाओं का जनसंख्या के अनुपात में विकास
2. रोजगार के संसाधनों का विकेन्द्रीकरण
3. यातायात एवं परिवहन सुविधाओं का नियोजित विकास
4. कृषि उपज पर आधारित उद्योग–धन्धों का विकास
5. उच्च स्तर की चिकित्सकीय एवं शिक्षण सुविधाओं का विकास
6. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण
7. नियोजित आवसीय कालोनियों का विकास
8. जल निकासी की उचित व्यवस्था
9. कूड़ा–कचरा प्रबन्धन हेतु उपयुक्त रणनीति का विकास
10. सुरक्षा की उचित व्यवस्था

निष्कर्ष

नगर के विकास के साथ ही उपान्त प्रदेश विकसित होने लगता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नगर एवं गांव से जुड़ा रहता है। यहां ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की सुविधाऐं व कार्य मिलते हैं। नगर का फैलाव इसके विकास में तीव्रगति से परिवर्तन लाता है। बागपत कस्बा की अवस्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीप है। यहां पर दिल्ली–सहारनपुर राष्ट्रीय सड़क मार्ग ने इसके उपान्त प्रदेश को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सड़क मार्गो के सहारे–सहारे इस नगर का फैलाब सबसे अधिक हुआ है। नगरी उपान्त प्रदेश में अद्यःसंरचनात्मक विकास सबसे अधिक हुआ है, जिसका प्रमुख कारण वृहत एवं लघु उद्योग–धन्धों हेतु पर्याप्त भूमि, सस्ता श्रम तथा कच्चा माल की उपलब्धता इत्यादि प्रमुख है। यहां पर द्वितीयक क्रिया–कलापों में 27. 45 प्रतिशत तथा तृतीयक क्रिया–कलापों में 13.83 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है, जबकि 58.72 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्रिया–कलापों में संलग्न है। आश्रित जनसंख्या यहां पर 51.15 प्रतिशत तथा कार्यशील जनसंख्या 48.85 प्रतिशत है। सेवा केन्द्रों के विकसित होने से यहां पर औसत अन्तरालन तथा जनसंख्या निर्भरता कम हो रही है। यहां पर उच्च क्रम की सेवाओं का धीरे–धीरे विकास हो रहा है। यहां पर अन्य उपयोग की भूमि के क्षेत्र में 1991–2011 की अवधि में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तकनीकी सुविधाओं के विकसित होने से नगरीय उपान्त प्रदेश का विकास तीव्रगति से हुआ है। यहां पर

नगरीकरण की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.83 प्रतिशत है, जो नगरीय उपान्त प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती है।

सुझाव

नगरीय उपान्त प्रदेश के संपोषणीय विकास हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. नई आवसीय कालोनियों का नियोजित विकास।
2. यातायात एवं परिवहन सुविधाओं की उचित व्यवस्था तथा नगरों से सम्पर्क
3. संसाधनों के संरक्षण एवं नवीनीकरण हेतु उपयुक्त रणनीति का विकास
4. बेरोजगारी एवं गरीबी के स्तर को कम करने हेतु उद्योग–धन्धों का विकास तथा तकनीकी शिक्षा का विकास
5. कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु समन्वित कृषि का विकास
6. पर्यावरणीण समस्याओं के समाधान हेतु वृक्षारोपण
7. वित्त की सुविधा हेतु वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबन्धन तथा उद्योग–धन्धों की स्थापना हेतु रियायती दर पर ऋण व अनुदान की सुविधा
8. पलायन रोकने हेतु आवश्यक सुविधाओं का उपान्त प्रदेश में विकास

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Goyal, Neha (2011)- "Dynamic Planning and Development of peri Urban Areas- A Case Study of Faridabad City', Institute of Rown Planners Indian Jorunal Vol-3, No-8, July-Sept-P 15-20.*
2. *Munsum, Kim (2012) "Peri-Urbanization and its impact on Rural livelihoods in Mumbai's Urban fringe" 48th ISOCARP Congress 2012.*
3. *A. Dariel Maina Thuo (2013)- "Unsettled Settled Spaces: Searching for a Theoretical Home for Rural-Urban Fringes', International Journal of Scientific and Research Publication Vol. 3, issue 7, July 2013, ISSN 2250-3153.*
4. *Kamal Asif (2014)- Encroachment of Agricultural land in Rurban Centers: fringe areas of Aligarh City, India-Process and Parameters", Asian Geographer, Vol. 31, issue 2, P.129-148.*
5. *Nisha (2015)- "Delineation of Rural Urban Fringe of Indian Cities : A Case Study of Jammu City", IOSR, Journal of Humanities and Social Science, Vol 20, Issue 4, p. 105-115.*
6. *Kolhe, N.P. and Dhote, K.K (2016)-Rurban centers: The New Dimension of Urbanism" Procedia Technology, Vol-24, p 1699-1705.*
7. *Nengroo ZA, Shah AH Bhatt, M.S. (2017)- "Dynamics of land use change in Rural-Urban fringe- A case study of Srinagar City", Environmental Science, An Indian, Journal, ISSN 0974-7451, VOl-4, p. 142.*
8. *Goswami, Mrinalini (2018)- "Conceptualizing Peri-Urban-Rural Landscape Change for Sustainable Management " Working paper 425, ISBN 978-81-7791-2814, The Institute for social and Economic Change Bangalore.*
9 *Kumar, Chandan And Sinha, B.R.K. (2019)- "Concepts and Approaches for Delineating the Rural-Urban Fringe" , NGJI, An International Peer Reviewed Journal, NGSI-BHU, ISSN: 0027-9374/2019/1712, Vol-65, No-3, Sept.*